



## GACs करेंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायतों का समाधान

### प्रलिस के लिये:

सोशल मीडिया, साइबर सुरक्षा भारत पहल, साइबर स्वच्छता केंद्र, ऑनलाइन साइबर अपराध रपिर्टिंग पोर्टल, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

### मेन्स के लिये:

सोशल मीडिया से संबंधित पहल।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने तीन **शिकायत अपील समितियों (GACs)** के गठन को अधिसूचित किया जो **सोशल मीडिया** और अन्य इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ता की शिकायतों का समाधान करेंगी।

- पैनल को इन प्लेटफॉर्म द्वारा लिये गए सामग्री मॉडरेशन-संबंधी नरिणयों की देख-रेख करने और उन्हें रद्द करने का भी अधिकार होगा।

## GACs क्या हैं?

### संघटन:

- तीनों GACs में से प्रत्येक में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जो विभिन्न सरकारी संस्थाओं और उद्योग से सेवानवृत्त वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जिनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये होगा।
  - पहला पैनल:** इसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र** का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा।
  - दूसरा पैनल:** इसकी अध्यक्षता **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** में नीति एवं प्रशासन प्रभाग का प्रभारी संयुक्त सचिव करेगा।
  - तीसरा पैनल:** इसकी अध्यक्षता **इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY)** का एक वरिष्ठ वैज्ञानिक करेगा।

### वविदों का समाधान:

- GAC दो प्रकार के वविदों का नपिटान करेगी:
  - अभवि्यक्त की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार सहित वधि और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन।
    - एक मंच के सामुदायिक दिशा-नरिदेशों और उपयोगकर्ता के बीच संवदिात्मक वविद।

### कार्य:

- GAC प्रौद्योगिकी क्षेत्र के नियामक के एक घटक के रूप में भी काम करेगी जैसे MeitY द्वारा भविष्य के डिजिटल इंडिया बलि के अनुसार स्थापति करने का अनुमान है, यह **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** को प्रतस्थापति करेगा।
- GACs एक ऑनलाइन वविद समाधान तंत्र अपनाएगी जिसमें पूरी अपील प्रक्रिया, यानी इसके फाइलिंग से लेकर अंतिम नरिणय तक ऑनलाइन की जाएगी।
- सोशल मीडिया मध्यस्थ के शिकायत अधिकारी के नरिणय से असंतुष्ट किसी भी व्यक्त को तीस दिनों की अवधि के भीतर GAC को अपील दायर करने की अनुमति होगी।
  - अपील प्राप्त होने के एक महीने के भीतर GAC को इस पर वधिार करना होगा और नरिणय देना होगा।

### महत्त्व और इसकी आवश्यकता:

- GAC इस समग्र नीति और वधिकि ढांचे का एक महत्त्वपूर्ण हसिसा है, यह इसलिये आवश्यक है ताकियह सुनश्चिति कियि जा सके कि भारत में इंटरनेट खुला, सुरक्षित, वशिवसनीय और जवाबदेह हो।
- बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान नही कियि जाने या इंटरनेट मध्यस्थों द्वारा असंतोषजनक ढंग से संबोधित कियि जाने के कारण GAC असतत्त्व में आई।
- इसके माध्यम से सभी इंटरनेट प्लेटफॉर्मों और मध्यस्थों का अपने उपभोक्ताओं के प्रत जवाबदेही सुनश्चिति कियि जाने की उम्मीद है।

### आलोचना:

- प्रस्ताव की पहले इस चर्चा के कारण आलोचना की गई थी कि सरकार द्वारा नियुक्त पैनल सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा किये गए सामग्री-मॉडरेशन निर्णयों को निर्धारित करने में सक्षम होंगे।

## साइबर सुरक्षा हेतु सरकार की वर्तमान पहल:

- [साइबर सुरक्षा भारत पहल](#)
- [साइबर सवच्छता केंद्र](#)
- [ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल](#)
- [भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र \(I4C\)](#)
- [राष्ट्रीय अतिसंवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र \(National Critical Information Infrastructure Protection Centre- NCIIPC\)](#)

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसिके लयिे साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनविर्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाताओं
2. डेटा केंद्र
3. कॉर्पोरेट नकियाय

नीचे दयिे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयिे:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न: 'सामाजकि संजाल स्थल' (Social Networking Sites) कया हैं और इन स्थलों से कया सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं? (मुख्य परीक्षा, 2013)

## [स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)